



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 19, 2008—जुलाई 25, 2008 (आषाढ़ 28, 1930)  
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 19, 2008—JULY 25, 2008 (ASADHA 28, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .....	817	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	673	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	9	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .....	5507
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ...	885	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस .....	381
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .....	*	भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं .....	3925
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस .....	165
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) .....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक .....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .....	*		

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	817	than the Administration of Union Territories).....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	673	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	9	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	885	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government	5507
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....	381
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.....	3925
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	165
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.....	*

\*Folios not received.

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

**[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]**

वस्त्र मंत्रालय

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय

नई दिल्ली-110066, दिनांक 17 जून 2008

संकल्प

सं. के-12012/5/16/2006-पी एण्ड आर--अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड का दिनांक 8 सितम्बर, 2006 के समसंख्यक संकल्प द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया गया था। भारत सरकार ने दिनांक 8 सितम्बर, 2006 (क्रमांक 1, 3, 5 एवं 7 को छोड़कर) 23 अक्टूबर, 2006, 22 एवं 27 नवम्बर, 2006, 5, 21 दिसम्बर, 2006, (क्रमांक 2 को छोड़कर) और 22 दिसम्बर, 2006 (क्रमांक 5 को छोड़कर) 5 एवं 10 जनवरी, 2007, 1 फरवरी, 2007 (क्रमांक 1 को छोड़कर) और 14 फरवरी, 2007 (क्रमांक 2, 3, 4, 7, 8, 9 और 10 को छोड़कर) 2, मार्च, 2007 (क्रमांक 2 को छोड़कर) 7, 9 मार्च, 2007, 8 मई, 2007 (क्रमांक 2 को छोड़कर) 16 मई, 2007, 25 जुलाई, 2007, 3 और 29 अगस्त, 2007, 11 सितम्बर, 2007, 24 सितम्बर, 2007, 15 अक्टूबर, 2007, 2 नवम्बर, 2007, 11, 12 एवं 25 मार्च, 2008 और 8 मई, 2008 के संकल्प द्वारा गठित मौजूदा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्यों को यथावत बनाए रखते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को नए गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है :--

1. श्री तेजवीर सिंह भाटी,  
ग्राम एवं पोस्ट - अस्तोली  
जिला गौतम बुद्ध नगर,  
उत्तर प्रदेश
2. श्री जावेद उर्फ़ी,  
3/4, शौकत अली रोड  
इलाहाबाद

पुनर्गठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में अध्यक्ष, सदस्य सचिव सहित 24 सरकारी सदस्यों तथा 53 गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करते हुए बोर्ड की वर्तमान संख्या 78 सदस्य हो जाएगी।

तथापि, दिनांक 8 सितम्बर, 2006 के संकल्प में दर्ज अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें वही रहेंगी तथा उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डॉ. संदीप श्रीवास्तव  
अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 2008

सं. 7-2/2008-यू 3 ए--चूंकि राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति (आंध्र प्रदेश) के कुलाधिपति, डॉ. वी. आर. पंचमुखी, का कार्यकाल दिनांक 15 जून, 2008 को समाप्त हो रहा है, भारत सरकार राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति (आंध्र प्रदेश) के संगम ज्ञापन तथा नियमावली के नियम 2, 32 तथा 33 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए प्रज्ञानवाचस्पति डॉ. जे. वी. पटनायक को 5 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति (आंध्र प्रदेश) का कुलाधिपति नियुक्त करती है जो कि 16 जून, 2008 अथवा कार्यालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख जो भी बाद में हो, से लागू होगा।

2. कुलाधिपति अपनी शक्तियों का प्रयोग विद्यापीठ के संगम ज्ञापन तथा नियमों के आधार पर करेंगे।

उपमन्यु बसु  
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 2008

संकल्प

सं. एफ 7-5/2008-यू 5--भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के संगम ज्ञापन एवं नियमों में प्रावधानित नियम 3 और 6 के अंतर्गत भारत सरकार निम्नलिखित समाज वैज्ञानिकों को तत्काल प्रभाव से तीन वर्षों की अवधि के लिए परिषद के सदस्यों के रूप में नामित करती है :--

1. प्रोफेसर शरीत भौमिक,  
टी. आई.एस.एस., मुम्बई
2. प्रोफेसर कमल मित्रा चिनोय,  
एस.आई.एस., जे.एन.यू., नई दिल्ली
3. प्रोफेसर रवि एस. श्री वास्तव,  
सी.एस.आर.डी., जे.एन.यू., नई दिल्ली
4. प्रोफेसर गोपाल गुरु,  
जे.एन.यू., नई दिल्ली
5. प्रोफेसर विरजीनियस खाखा,  
दिल्ली स्कूल ऑफ इकानोमिक्स

6. प्रोफेसर अपूर्वा बरुआ,  
पूर्वाञ्चल पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग

7. प्रोफेसर उदयन मिश्रा,  
डिब्रुगढ़ विश्वविद्यालय

8. प्रोफेसर सशीज हेगड़े  
हैदराबाद विश्वविद्यालय

9. प्रोफेसर मालविका कपूर  
बंगलौर

10. प्रोफेसर वी. गीता  
तमिलनाडु

11. प्रोफेसर फातिमा अली खान  
उस्मानिया विश्वविद्यालय

12. प्रोफेसर योगेन्द्र यादव  
सी.एस.डी.एस.

13. डॉ. वसन्ती रमन  
सी. डब्ल्यू.डी.एस.

14. श्री सुदीप बैनर्जी  
कुलाधिपति, एन.यू.ई.पी.ए.

15. प्रोफेसर एस.पी. सिंह  
पूर्व अध्यक्ष, इतिहास विभाग  
एल. एन. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

16. प्रोफेसर राम सखा गौतम,  
संस्थापक अध्यक्ष  
मध्य प्रदेश समाज विज्ञान अनुसंधान संस्थान,  
उज्जैन, मध्य प्रदेश

17. श्री अमरेश मिश्रा,  
इतिहासकार

18. प्रोफेसर उत्तम बाजीराव भोइटे  
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग,  
पूर्व कुलपति, यशवन्तराव चव्हाण  
महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक

उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित को भारत सरकार के प्रतिनिधियों के रूप में नामित किया जाता है :--

1. श्री आर.पी. अग्रवाल,  
सचिव, उच्चतर शिक्षा  
भारत सरकार
2. भारत के महापंजीयक
3. श्री राम शरण जोशी,  
उपाध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा
4. श्री उदय नारायण सिंह,  
निदेशक, सी.आई.आई.एल., मैसूर
5. प्रोफेसर कृष्ण कुमार,  
निदेशक, रा.शै.अनु. एवं प्र. परिषद

6. श्री सनत कुमार राय,  
संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार,  
मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सुनिल कुमार  
संयुक्त सचिव

दिनांक 27 जून 2008

// सं. एफ. 9-11/2000-यू. 3 (ए)--जबकि "प्रावरा आयुर्विज्ञान संस्थान", पो.ओ. लोनी जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र जिसमें निम्नलिखित संघटक शामिल हैं, को इस मंत्रालय के दिनांक 29 सितम्बर, 2003 की समसंख्यक अधिसूचना के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया था उसमें कतिपय शर्तें थीं जिनकी तीन वर्षों के पश्चात् समीक्षा की जाएगी:--

- (1). रूरल मेडिकल कालेज, लोनी
- (2) रूरल डेंटल कालेज, लोनी
- (3) कालेज ऑफ फिजियोथेरेपी, लोनी
- (4) कालेज ऑफ नर्सिंग, लोनी
- (5) सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी
- (6) सेंटर फॉर सोशल मेडिसन

2. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस प्रयोजनार्थ गठित विशेषज्ञ समिति के माध्यम से उपरोक्त लिखित संघटक इकाईयों सहित "प्रावरा आयुर्विज्ञान संस्थान" के कार्यक्रम की समीक्षा की है।

3. और जबकि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "प्रावरा आयुर्विज्ञान संस्थान" को स्थायी आधार पर 'समविश्वविद्यालय' का दर्जा जारी रखने की सिफारिश की है;

4. अतः अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर "प्रावरा आयुर्विज्ञान संस्थान" जिसमें उपरोक्त लिखित संघटक इकाईयां भी शामिल हैं, को इस मंत्रालय के दिनांक 29 सितम्बर, 2003 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुसार उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करती है बशर्ते कि वे समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय चिकित्सा परिषद और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा निर्धारित मानदण्डों और दिशा-निर्देशों का अनुपालन करें जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थाओं पर लागू हैं। उक्त पैरा 4 में की गई घोषणा आगे उन शर्तों पर की जाएगी जिनका इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्र. सं. 4 में उल्लेख किया गया है।

सुनिल कुमार  
संयुक्त सचिव

सं. एफ. 9-42/2005-यू. 3 (ए)--जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी उच्चतर अध्ययन संस्थान को "समविश्वविद्यालय" घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि नेहरू ग्राम भारतीय, कोटवा-जामुनीपुर, डबवाली जिला इलाहाबाद से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा के अंतर्गत समविश्वविद्यालय के दर्जे की मांग की गई थी।

3. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त प्रस्ताव की जांच की है और दिनांक 12 जून, 2007 के अपने पत्र संख्या एफ. 6-54/2005 (सी.पी.पी-1) के माध्यम से नेहरू ग्राम भारती को शुरुआत के 3 वर्ष के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत 'समविश्वविद्यालय' का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की है।

4. अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर राजीव गांधी स्नातकोत्तर कालेज सहित नेहरू ग्राम भारती को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ 3 वर्ष की अवधि के लिए समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है जो कि उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि से उक्त कालेज स्वयं को अपने सम्बद्ध विश्वविद्यालय अर्थात् छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से असंबद्ध कर लेगा। नेहरू ग्राम भारती को दिया गया दर्जा इस शर्त के अधीन होगा कि 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ समिति की सहायता से इस दर्जे की समीक्षा करेगा। इस दर्जे की पुष्टि तभी होगी जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की जांच और मूल्यांकन रिपोर्ट पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी सिफारिशें दे देगा।

5. उपर्युक्त पैरा 4 में की गई उद्घोषणा इस शर्त के भी अधीन है जिसका उल्लेख इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम संख्या 3 पर किया गया है।

6. न तो भारत सरकार और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेहरू ग्राम भारती या इसकी अंगीभूत शिक्षण इकाई को योजनागत और योजनेतर सहायता अनुदान प्रदान करेंगे।

सुनिल कुमार  
संयुक्त सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जुलाई 2008

संकल्प

सं. 2-1/2008-हिन्दी--इस मंत्रालय के दिनांक 20.06.2005 के संकल्प सं. 2-1/2003-हिन्दी के अनुक्रम में भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का कार्यकाल 20 जून, 2009 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। साथ ही, प्रो. रामदेव भण्डारी और श्रीमती कुमकुम राय को क्रमशः श्री अशोक वाजपेयी और श्री मधुकर उपाध्याय के स्थान पर संस्कृति मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री के कार्यालय, समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

लव वर्मा  
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES  
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER  
(HANDICRAFTS)

New Delhi-110006, the 17th June 2008

RESOLUTION

No. K-12012/5/16/2006-P&R.—The All India Handicrafts Board was reconstituted vide resolution of even No. dated 08th September, 2006 for a tenure of two years. The Government of India has decided to induct the following as new non official members of All India Handicrafts Board while retaining all officials and non-official members of the existing All India Handicrafts Board constituted vide resolution dated 08th September, 2006 (except Sl. No. 1, 3, 5 & 7) 23rd October, 2006, 22nd November, 2006 and 27th November, 2006, 5th, 21st December, 2006 (except Sl. No. 2) and 22nd December, 2006 (except Sl. No. 5) 5th & 10th January 2007, 1st February, 2007 (except Sl. No. 1) and 14th February, 2007 (except Sl. No. 2, 3, 4, 7, 8, 9 & 10), 2nd March, 2007 (except Sl. No. 2), 7th & 9th March 2007, 8th May, 2007 (except Sl. No. 2), 16th May, 2007, 25th July 2007, 3rd & 29th August 2007, 11th September, 2007, 24th September, 15th October, 2007, 2nd November 2007, 11th & 12th March 2008, 25th March 2008 and 8th May 2008.

1. Shri Tejveer Singh Bhati,  
Village & Post—Astoli, Distt.  
Gautam Budh Nagar,  
Uttar Pradesh.
2. Shri Javed Urfi,  
3/4 Shaukat Ali Road,  
Allahabad.

The present strength of the Board shall be 78 Members comprising of Chairman, 24 official Members including Member Secretary and 53 Non-official Members, in the reconstituted All India Handicrafts Board.

All other terms and conditions recorded in the resolution dated 08th September 2006 will, however, remain same and unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

Dr. SANDEEP SRIVASTAVA  
Addl. Development Commissioner (Handicrafts)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT  
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 11th June 2008

No. 7-2/2008-U. 3A.—As the term of office of Dr. V. R. Panchamukhi, Chancellor (Kuladhipati) of the Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati (Andhra Pradesh) comes to an end on 15th June, 2008, in exercise of the powers vested

under Rule 2, 32 and 33 of the Memorandum of Association and Rules of the Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati (Andhra Pradesh), the Government of India is please to appoint Prajnanavacaspasi Dr. J. B. Patanaik as the Chancellor (Kuladhipati) of the Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati (Andhra Pradesh) for a period of five years with effect from 16th June 2008 or from the date he takes over charge of office; whichever is later.

2. The Chancellor (Kuladhipati) will exercise his powers in accordance with the Memorandum of Association and Rules of the Vidyapeetha.

UPAMANYU BASU  
Director

New Delhi, the 27th May 2008

RESOLUTION

No. F. 7-5/2008-U-5.—Under Rule 3 and 6 of the Memorandum of Association and Rules of the Indian Council of Social Science Research, New Delhi, the Government of India nominates the following Social Scientists as Members of the Council for a period of three years with immediates effect :—

1. Prof. Sharit Bhowmik  
TISS, Mumbai
2. Prof. Kamal Mitra Chenoy  
SIS, JNU, New Delhi
3. Prof. Ravi S. Srivastava  
CSRD, JNU, New Delhi
4. Prof. Gopal Guru  
JNU, New Delhi
5. Prof. Virginius Xaxa  
Delhi School of Economics
6. Prof. Apurba Barua  
NEHU, Shillong
7. Prof. Udayon Misra  
Dibrugarh University
8. Prof. Sasheej Hegde  
University of Hyderabad
9. Prof. Malvika Kapur  
Bangalore
10. Prof. V. Geetha  
Tamil Nadu
11. Prof. Fatima Ali Khan  
Osmania University
12. Prof. Yogendra Yadav  
CSDS
13. Dr. Vasanthi Raman  
CWDS

14. Shri Sudeep Banerjee  
Chancellor, NUEPA
15. Prof. S. P. Singh  
Former Head of the Department of History  
L. N. Mithila University, Darbhanga
16. Prof. Ram Sakha Gautam  
Founder President  
M. P. Instt. of Social Science Research  
Ujjain, Madhya Pradesh
17. Mr. Amaresh Misra  
Historian
18. Prof. Uttam Bajirao Bhoite  
Prof. & Head of the Department of Sociology  
Former Vice Chancellor, Yashwantrao Chavan  
Maharashtra Open University, Nasik

In addition, the following are nominated as Representatives of the Government of India :—

1. Shri R. P. Agrawal  
Secretary, Higher Education  
Government of India
2. Registrar General of India
3. Shri Ram Sharan Joshi  
Vice Chairman, KHS, Agra
4. Shri Udai Narain Singh  
Director, CIIL, Mysore
5. Prof. Krishna Kumar  
Director, NCERT
6. Shri Sanat Kumar Ray  
JS&FA, MHRD

#### ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SUNIL KUMAR  
Jt. Secy.

The 27th June 2008

No. F. 9-11/2002-U. 3.—Whereas “Pravara Institute of Medical Sciences (PIMS)”, P.O. Loni, Distt. Ahmednagar, Maharashtra comprising of following constituent units was declared as an institution “Deemed to be university” under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 vide this Ministry's notification of even number dated the 29th September, 2003 subject to certain conditions that included a review after three years;

- (1) Rural Medical College, Loni.
- (2) Rural Dental College, Loni.
- (3) College of Physiotherapy, Loni.

- (4) College of Nursing, Loni.
- (5) Centre for Biotechnology.
- (6) Centre for Social Medicines.

2. And whereas, the UGC has reviewed the functioning of the “Pravara Institute of Medical Sciences (PIMS)” consisting of the above mentioned constituent units through an Expert Committee constituted for this purpose;

3. And, Whereas, on the basis of the report of the Expert Committee, the UGC have recommended continuation of the status of ‘Deemed-to-be-University’ to “Pravara Institute of Medical Sciences (PIMS)”.

4. Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, and on the advice of the UGC in the matter, does hereby accord approval to the continuance of “Pravara Institute of Medical Science (PIMS)” comprising of aforesaid constituent units as an institution “deemed-to-be-university” for the purpose of the aforesaid Act, strictly in terms of this Ministry's notification of even number dated the 29th September, 2003 subject to the conditions that they will adhere to the norms and guidelines prescribed by UGC and the Medical Council of India, Dental Council of India and other Statutory Councils, from time to time, as per applicable to the institutions declared as “deemed-to-be-universities” under Section 3 of the UGC Act, 1956. The declaration made in para 4 above shall be subject to further conditions that are mentioned at Sl. No. 4 of the endorsement of this notification.

/s/ SUNIL KUMAR  
Jt. Secy.

No. F. 9-42/2005-U. 3 (A).—Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a “deemed-to-be-university”.

2. And whereas, a proposal was received from Nehru Gram Bharati, Vishwavidyalaya Kotwa-Jamunipur, Dubwali Distt. Allahabad seeking status of “deemed-to-be-university” under Section 3 of the UGC Act, 1956.

3. And whereas, the University Grants Commission have examined the said proposal and vide their communication No. F. 6-54/2005 (CPP-I) dated the 12th June, 2007 have recommended conferment of status of “deemed-to-be-university” to Nehru Gram Bharati Vishwavidyalaya under Section 3 of the UGC Act, 1956, initially for a period of 3 years;

4. Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission (UGC), hereby declare Nehru Gram Bharati Vishwavidyalaya comprising of Rajiv Gandhi P. G. College a period of 3 years, with effect from the date on which the aforesaid College is disaffiliated from its affiliating university, viz., Ch. Sahuji Maharaj University, Kanpur, subject to the condition that

the status conferred upon the Nehru Gram Bharati Vishwavidyalaya will be reviewed by the UGC with the help of an Expert Committee before the expiry of the 3-year period. The status shall be confirmed only on the basis of the inspection and assessment report of UGC's Expert Review Committee and subjected to nullification of its present shortcoming as pointed out by the Expert Committee.

5. The declaration made in para 4 above is subject to further conditions mentioned at Sr. No. 3 of the endorsement to this Notification;

6. Neither the Government of India nor the University Grants Commission shall provide any Plan and Non-Plan grant-in-aid to Nehru Gram Bharati or its constituent teaching units.

SUNIL KUMAR  
Jt. Secy.

---

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 2nd July 2008

RESOLUTION

No. F.2-1/2008-Hindi.—In continuation of this Ministry's Resolution No. 2-1/2003-Hindi dated 20.6.2005 the

Government of India has decided to extend the tenure of the Hindi Salahakar Samiti of Ministry of Culture upto 20th June 2009. Besides, Prof. Ramdeo Bhandari & Smt. Kumkum Rai in place of Shri Ashok Vajpayee & Shri Madhukar Upadhyay respectively have been nominated as Members of the Hindi Salahakar Samiti of Ministry of Culture.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all the members of the Committee, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliament Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Committee of Parliament on Official Language, Comptroller and Auditor General of India and all the Ministries/Departments of the Government of India.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

LOV VERMA  
Jt. Secy.